

## वशेष अदालतें

### वशेष अदालत कसै कहा जाता है?

#### पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आदेश दिया कि सांसदों के लंबे समय से लंबित मुकदमों को तेज़ी से नपिटाने के लिये देश भर में वशेष अदालत स्थापति की जाएँ।
- इसके पश्चात् 11 राज्यों में वशेष रूप से मौजूदा सांसदों और वधायकों की सुनवाई के लिये 12 वशेष अदालतें स्थापति की गईं।
- सितंबर, 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नयिकृत एमकिस क्यूरी (अदालत के मतिर) ने अपनी दो रिपोर्टों में इस बात पर प्रकाश डाला कि वधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिये अदालत द्वारा वशेष अदालतों का गठन करने के सर्वोत्तम पर्यासों के बावजूद, 2,556 सांसद और वधायकों से जुड़े लगभग 4,442 आपराधिक मामलों लंबित हैं।
- ये मामले अब 5,000 का आँकड़ा पार कर चुके हैं, जनिमें से 400 जघन्य अपराधों से संबंधित हैं।

#### इसके बारे में:

- एक वशेष अदालत वैसी अदालत है जिसका अधिकार क्षेत्र सीमित है और एक वशिष्ट भौगोलिक स्थान के बजाय कानून के एक वशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है।
- भारत में ये अदालतें वर्ष 1979 के वशेष न्यायालय अधिनियम के तहत स्थापति की गईं हैं।
- इन अदालतों की स्थापना वशिष्ट अपराधों जैसे प्रतभूत लेनदेन, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के खिलाफ अत्याचार, नशीले पदार्थों, [राष्ट्रीय जाँच एजेंसी \(NIA\) अधिनियम 2008](#) के उल्लंघन, भ्रष्टाचार आदि से संबंधित विभिन्न परीक्षणों के लिये की गई है।
- वशेष न्यायालयों की स्थापना और संचालन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- राज्यों में कानूनी ढाँचे को मज़बूत करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को 14वें वतित आयोग ने समर्थन दिया था, जिसमें 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) स्थापति करना शामिल था।
- इन अदालतों की स्थापना समाज के हाशिए और वंचित वर्गों से जुड़े मामलों को संभालने के लिये की गई थी।

#### संघटन:

- एक वशेष अदालत में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सहमति से उच्च न्यायालय, जनिके अधिकार क्षेत्र में वशेष अदालत स्थित है, के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित एक उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश शामिल होंगे

#### क्षेत्राधिकार:

- वशेष क्षेत्राधिकार कुछ प्रकार के मामलों पर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है जैसे दवािलयिपन, सरकार के खिलाफ दावे, प्रोबेट, पारविरिक मामले, आप्रवासन, और सीमा शुल्क, या या अधिकतम राशिया मूल्य वाले मामलों की सुनवाई के लिये अदालत के अधिकार पर सीमाएँ। वशेष क्षेत्राधिकार को सीमिति क्षेत्राधिकार के रूप में भी जाना जाता है।
- वशेष न्यायालय एक बहुत ही संकीर्ण अधिकार क्षेत्र में मामलों की सुनवाई करते हैं और न्यायाधीश एक वशिष्ट अवधि के लिये कार्य करते हैं, जबकि संवैधानिक न्यायालय का मुख्य अधिकार यह तय करना है कि जनि कानूनों को चुनौती दी गई है क्या वे असंवैधानिक हैं, उदाहरण के लिये- क्या वे संवैधानिक रूप से स्थापति अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ संघर्ष करते हैं।

#### उदाहरण:

- उदाहरण के लिये, उच्च न्यायालयों के परामर्श से [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति \(अत्याचार नविरण \(PoA\)\) संशोधन अधिनियम, 2015](#) के तहत संबंधित मुद्दों से नपिटने के लिये अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, कुछ वशेष अदालतें संबंधित सरकारों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए स्थापति की जाती हैं।
- अधिनियम में राज्य सरकार को प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक वशेष न्यायालय की पहचान करने की आवश्यकता है, जसि सत्र न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है, जसिमें इस अधिनियम के तहत कम मामले हैं। यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक राज्य में ऐसे न्यायालयों के गठन की उपेक्षा न की जाए।

## फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTCs) क्या हैं?

- **FTCs वे विशेष अदालत** हैं जो मुकदमे में तेज़ी लाने और मामलों के नपिटान के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं, विशेष रूप से वैसे मुकदमे जो लंबे समय से लंबित हैं।
- FTCs का मुख्य उद्देश्य नयिमति अदालतों में लंबित मामलों को कम करना और त्वरति न्याय सुनिश्चित करना है।
- फास्ट ट्रैक अदालतें अपराधिक मामलों, दीवानी मामलों और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों सहित कई प्रकार के मामलों की को संभालती हैं।

### वर्षिष न्यायालय सामान्य न्यायालयों से कैसे भिन्न होते हैं?

- वर्षिष न्यायालय कुछ मामलों के अलावा कई मायनों में सामान्य अदालतों से भिन्न होते हैं। वर्षिष न्यायालयों में, मुकदमे के बिना मामलों को खारजि कयि जाने की अधिक संभावना होती है, और यदि कोई सुनवाई होती है तो यह आमतौर पर सामान्य क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय की तुलना में अधिक तेज़ी से आयोजित की जाती है।
- इसके अलावा वर्षिष न्यायालय आम तौर पर सामान्य अदालतों के समान प्रक्रियात्मक नयिमों का पालन नहीं करते हैं।
- अक्सर ये अदालतें कानूनी प्रतिनिधित्व या यहां तक कि कानूनी प्रशिक्षण प्राप्त न्यायाधीशों के लाभ या खर्च के बिना काम करती हैं। वर्षिष अदालतों में काम करने वाले जज अलग-अलग पृष्ठभूमि और योग्यता के साथ एक विविध समूह हैं।
- सामान्य क्षेत्राधिकार न्यायालयों के विपरीत जहां न्यायाधीशों को योग्यता के आधार पर नियुक्त कयि जाता है, अधिकांश वर्षिष न्यायालयों के न्यायाधीशों को राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त कयि जाता है। इसके अतिरिक्त, वर्षिष न्यायालय के कई न्यायाधीश वकील नहीं होते हैं।

### न्यायाधिकरण और वर्षिष न्यायालयों के बीच अंतर:

- वर्षिष अदालत नयिमति अदालतों के समान है लेकिन केवल वर्षिषित मामलों से संबंधित है। न्यायाधिकरण के समान एक वर्षिष अदालत बनाई जाती है।
- हालांकि वर्षिष अदालतें उच्च न्यायालयों के मार्गदर्शन और नियंत्रण में आती हैं। जबकि न्यायाधिकरण वधियों के अंतर्गत बनाए गए हैं।
- नयिमति अदालतों पर बोझ कम करने के लिये न्यायाधिकरण और वर्षिष अदालतें स्थापित की गईं। हालांकि न्यायाधिकरण एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो वर्षिषित मामलों से नपिटने के लिये स्थापित कयि गया है।
- एक वर्षिष अदालत इसके समान है लेकिन यह अनविषय रूप से केवल एक अदालत है जहां सभी प्रक्रियाएँ लागू होती हैं।

## वर्षिष अदालतों के संबंध में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव:** भारत में वर्षिष अदालतें अक्सर नयिमति अदालतों के समान चुनौतियों का सामना करती हैं, क्योंकि उन्हें आमतौर पर नए बुनियादी ढाँचे के रूप में स्थापित करने के बजाय नरिदषिट कयि जाता है।
  - इससे न्यायाधीशों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, जिन्हें आवश्यक सहायक कर्मचारियों या बुनियादी ढाँचे के बिना उनके मौजूदा कार्यभार के अलावा अन्य श्रेणियों के मामले सौंपे जाते हैं। नतीजतन, इन वर्षिष अदालतों में मामलों के नपिटान की दर धीमी हो जाती है।
- **सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं का अभाव:** इसके अतिरिक्त, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को सरल कयि बिना या वर्षिष अदालतों को और अधिक सुव्यवस्थित कयि बिना तेज़ी से मामले का नपिटान नहीं कयि जा सकता है। ये चुनौतियाँ वर्षिष अदालतों की त्वरति सुनवाई प्रदान करने और भारत में मामलों के बैकलॉग को संबोधित करने की प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं।
- **दूसरों पर कुछ अपराधों की प्राथमिकता:** भारत में वर्षिष अदालतों की स्थापना अक्सर सरकार की न्यायिक और कार्यकारी दोनों शाखाओं द्वारा कयि गए तदर्थ नरिणयों द्वारा नरिधारित की जाती है। इस दृष्टिकोण का मतलब है कि कुछ श्रेणियों के अपराधों को अनयोजित ढंग से दूसरों की तुलना में तेज़ी से नपिटाने में प्राथमिकता दी जाती है।
- **सीमति क्षेत्राधिकार:** ये अदालतें एक वर्षिषित क्षेत्राधिकार के साथ स्थापित की जाती हैं, जो संबंधित मामलों से नपिटने की उनकी क्षमता को सीमति कर सकती हैं। इससे न्याय वरिण में देरी हो सकती है और कानूनों के लागू होने में नरितरता की कमी हो सकती है।
- **अन्य बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप:** वर्षिष अदालतें अक्सर राजनीतिक और बाहरी हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील होती हैं, जो उनकी स्वतंत्रता और नषिपक्षता को कमजोर कर सकती हैं।

## आगे की राह?

- **धन में वृद्धि:** भारत में वर्षिष अदालतों की स्थापना और रखरखाव के लिये अधिक धन आवंटित करने की आवश्यकता है। इससे इन अदालतों के सुचारू कामकाज के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा और संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
- **प्रशिक्षण और क्षमता नरिमाण:** वर्षिष अदालतों में न्यायाधीशों और कर्मचारियों को नयिमति प्रशिक्षण और क्षमता नरिमाण कार्यक्रम प्रदान कयि जाने चाहिये। इससे उन्हें नवीनतम कानूनी विकास के साथ अद्यतन रहने और जटिल मामलों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिये अपने कौशल में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- **स्वतंत्रता और नषिपक्षता:** वर्षिष अदालतों को स्वतंत्र और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त बनाया जाना चाहिये। न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता और अनुभव के आधार पर की जानी चाहिये न कि राजनीतिक विचारों के आधार पर। इससे न्याय प्रदान करने में नषिपक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- **अधिकार क्षेत्र का वसितार:** सरकार को और श्रेणियों के मामलों को कवर करने के लिये वर्षिष अदालतों के अधिकार क्षेत्र का वसितार करने पर विचार करना चाहिये। इससे नयिमति अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करने और न्याय देने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी।
- **प्रक्रियाओं का सरलीकरण:** मामलों के त्वरति नपिटान को सुनिश्चित करने के लिये वर्षिष अदालतों में प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को सरल बनाया जाना चाहिये। इसमें वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को अपनाना और अनावश्यक देरी को कम करना शामिल हो सकता है।

